भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना हुआ

आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में कवरेज 48.8% तक पहुंच जाएगा, जो 2021 में 24.4% था

सारांश

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (डब्ल्यूएसपीआर) 2024-26 के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। रिपोर्ट इस प्रगति का श्रेय प्रमुख सरकारी पहलों को देती है, जिसने लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और रोजगार सहायता जैसे लाभ प्रदान किए हैं।

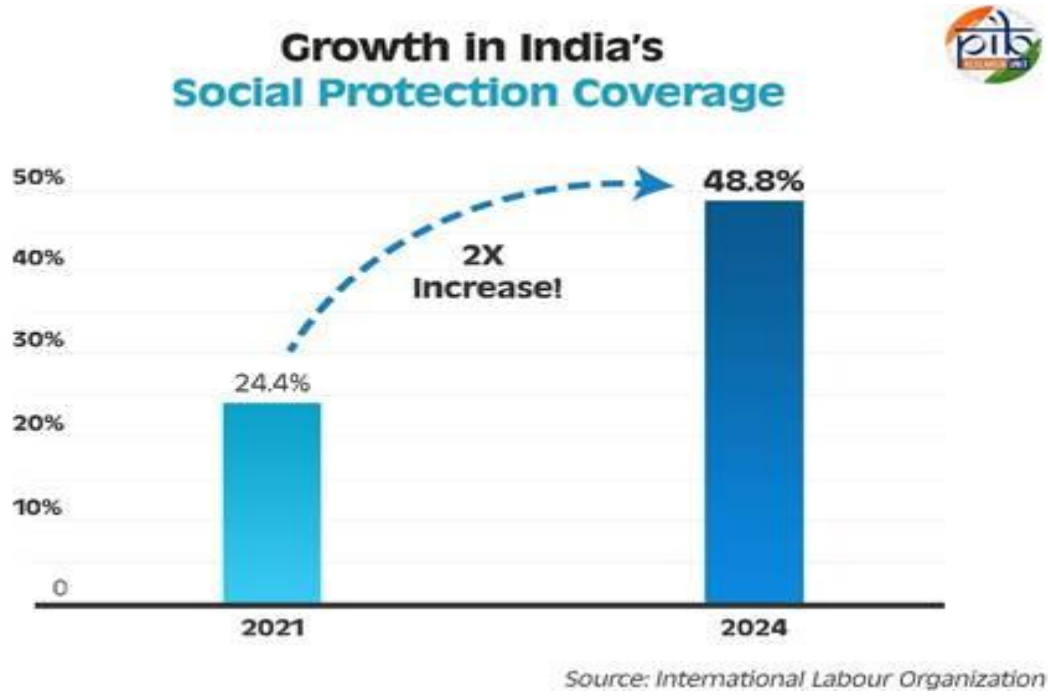

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, अब लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, चाहे वह नकद सहायता हो या वस्तु के रूप में। भारत की प्रगति ने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5 प्रतिशत की वृद्धि में भी योगदान दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी परिणामों को आकार देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट का अवलोकन

विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा समय-समय पर प्रकाशित एक व्यापक मूल्यांकन है, जो श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करती है, तथा विविध जनसंख्याओं के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी कवरेज, प्रभावशीलता और प्रगति की जांच करती है। नीतियों और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करके, यह अधिक मजबूत और समावेशी कल्याण प्रणालियों की दिशा में काम करने वाली सरकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करता है।

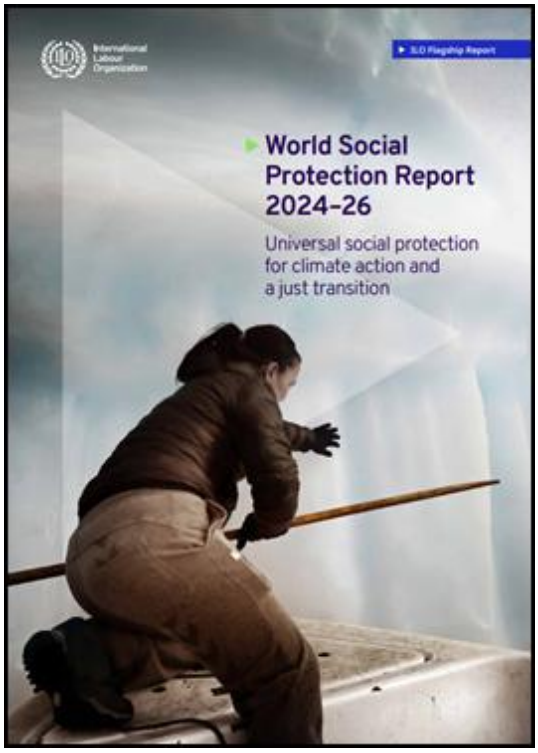

रिपोर्ट का 2024-26 संस्करण जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण और न्यायसंगत संक्रमण पर केंद्रित है। पहली बार, इसमें प्रवृत्ति डेटा को शामिल किया गया है, जो वैश्विक प्रगति पर अधिक गतिशील परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज, प्रदान किए गए लाभों और सार्वजनिक व्यय पर वैश्विक, क्षेत्रीय और देश-स्तरीय सांख्यिकी का एक व्यापक सेट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय सहायक रिपोर्ट वैश्विक निष्कर्षों को पूरक बनाती है और इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के विकास का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। यह सह-रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों पर विचार करते हुए प्रमुख चुनौतियों, प्राथमिकताओं और सामाजिक संरक्षण एवं जलवायु कार्रवाई के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालती है।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: प्रमुख सरकारी पहल

भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से काफी विस्तार हुआ है, जिसका उद्देश्य लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सहायता प्रदान करना है। इन पहलों ने देश भर में आजीविका में सुधार और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यहाँ कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और पहलें दी गई हैं:

आयुष्मान भारत

26 मार्च, 2025 तक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं। यह योजना देश भर में 24,810 सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शुरू की गई यह योजना कमजोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। दिसंबर 2024 तक 80.67 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्षित कवरेज के करीब है।

ई-श्रम पोर्टल

असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को शुरू की गई यह पहल श्रमिकों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करती है। 3 मार्च, 2025 तक, 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 53.68% महिलाएँ हैं।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

9 मई, 2015 को शुरू की गई एपीवाई का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ-साथ यह देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। 31 दिसंबर, 2024 तक 7.25 करोड़ लाभार्थियों ने एपीवाई में नामांकन कराया है, जिसकी कुल संचित राशि 43,369.98 करोड़ रुपये है।

गरीबी घटाना

पिछले दशक में, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सरकार के हस्तक्षेपों के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

भारत ने सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास शुरू किया

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 48.8% का आकलन भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें खाद्य सुरक्षा और आवास सहायता या राज्य द्वारा प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं जैसे वस्तुगत लाभों को शामिल नहीं किया गया है। इन कारकों के एकीकरण के साथ, भारत का वास्तविक सामाजिक सुरक्षा कवरेज काफी अधिक होने की उम्मीद है, जो चल रहे सुधारों और डेटा समेकन प्रयासों को दर्शाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए 19 मार्च, 2025 को भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास के चरण 01 की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारत के कल्याण परिदृश्य की अधिक समग्र तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डेटा को समेकित करना है। पहले चरण में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात सहित दस राज्यों को केंद्रीय स्तर पर डेटा समेकन के लिए पहचाना गया है।

इन प्रयासों के आधार पर, भारत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) सहित 34 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं में एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में एन्क्रिप्टेड आधार का उपयोग करके 200 करोड़ से अधिक रिकॉर्डों को संसाधित किया है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए आईएलओ के साथ उच्च स्तरीय वार्ता कर रहा है कि ये अतिरिक्त कल्याणकारी उपाय भविष्य के आकलनों में प्रतिबिंबित हों। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 353वीं आईएलओ गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान द्विपक्षीय चर्चा में, आईएलओ ने स्वीकार किया कि आवास और खाद्य सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के विस्तारित संकेतकों का हिस्सा हैं। आईएलओ ने ऐसी योजनाओं को अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

केंद्र, राज्य सरकारों और आईएलओ के बीच निरंतर सहयोग से, भारत अपने सामाजिक संरक्षण ढांचे को और अधिक परिष्कृत करने तथा अपने कल्याणकारी पहुंच की अधिक सटीक तस्वीर पेश करने के लिए तैयार है।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में भारत की प्रगति समावेशी कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 में रेखांकित कवरेज को दोगुना करना, लाखों लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में आयुष्मान भारत, पीएमजीकेएवाई और ई-श्रम पोर्टल जैसी प्रमुख पहलों के प्रभाव को रेखांकित करता है। सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास का शुभारंभ डेटा-संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देकर और मौजूदा आकलन में अंतराल को दूर करके इन प्रयासों को और मजबूत करता है। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से अपने सामाजिक सुरक्षा ढांचे को परिष्कृत करने का काम जारी रखे हुए है, इसलिए इसका दृष्टिकोण कल्याण विस्तार और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

संदर्भ:

- https://www.social-protection.org/gimi/Media.action?id=20154
- https://www.social-protection.org/gimi/Media.action?id=10982
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114866
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094581
- https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1827_Ddvmdr.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU30_xZbQzy.pdf?source=pqals
- https://pib.gov.in/PressReleseDetailmaspx?PRID=2086345®=3&lang=1

पडीफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

एमजी/केसी/जीके